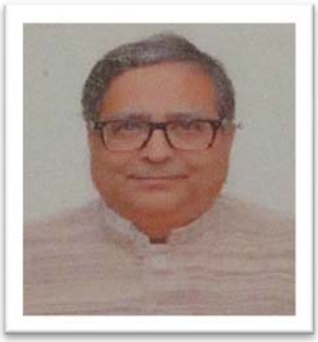

डॉ. टीसीए अनंत

डॉ. टीसीए अनंत ने 14 जनवरी, 2019 को संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य के रूप में कार्यभार ग्रहण किया, इससे पहले वे दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स (डीएसई), दिल्ली विश्वविद्दालय में अर्थशास्त्र विभाग में प्रोफेसर और विभागाध्यक्ष थे। उन्होंने पूर्व में 2010 से 2018 तक भारत के मुख्य सांख्यिकीविद् (सीएसआई) और सचिव, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, 2006 से 2009 तक भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद (आईसीएसएसआर) के सदस्य सचिव के पद पर कार्य किया।

मुख्य सांख्यिकीविद (सीएसआई) के रूप में उनके कार्यकाल के दौरान, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय (सीएसओ) ने औधोगिक उत्पादन सूचकांक (आईआईपी) और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) की श्रृंखला के साथ-साथ आधार वर्ष 2011-12 के लिए भारतीय राष्ट्रीय लेखा प्रणाली को संशोधित किया; राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन (एनएसएसओ) ने रोजगार पर एक नया नियमित सर्वेक्षण प्रारंभ किया; और अधीनस्थ सांख्यिकी सेवा और भारतीय सांख्यिकी सेवा दोनों के कैडर संरचनाओं की समीक्षा की जो चिरकाल से लंबित थी। मुख्य सांख्यिकीविद् के रूप में, प्रो. अनंत ने श्रम सांख्यिकीविदों के 19वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता की; संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकीय आयोग (यूएनएससी) के तहत "प्रगति के व्यापक उपाय" और "अंतर्राष्ट्रीय तुलनात्मक कार्यक्रम के 2011 दौर का मूल्यांकन" पर फ्रेंड्स ऑफ दी चेयर ग्रुप की सह-अध्यक्षता की; और संयुक्त राष्ट्र महासचिव द्वारा स्थापित डेटा रिवोल्यूशन पर अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञ सलाहकार समूह का सदस्य रहे।

आईसीएसएसआर के सदस्य सचिव के रूप में, प्रो. अनंत ने आईसीएसएसआर की चौथी समीक्षा कराने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने अल्पसंख्यक बहुल जिलों का पहले बेसलाइन सर्वेक्षण करने में आईसीएसएसआर के अनुसंधान प्रयासों को भी गति प्रदान की।

प्रो. अनंत ने कॉर्नेल विश्वविद्दालय से अर्थशास्त्र में पीएचडी और दिल्ली स्कूल ऑफ इकनोमिक्स से अर्थशास्त्र में एमए किया। वह मिशिगन स्टेट यूनिवर्सिटी, यूएसए में अर्थशास्त्र में सहायक प्रोफेसर और फिर दिल्ली स्कूल ऑफ इकनोमिक्स में रीडर और फिर प्रोफेसर थे, जहां उन्होंने एमए कार्यक्रम में लॉ एंड इकोनॉमिक्स पर पाठ्यक्रम शुरू किया। उनके शोध में श्रम अर्थशास्त्र, औधोगिक अर्थशास्त्र, विधि और अर्थशास्त्र और अर्थमिति सहित कई क्षेत्र शामिल हैं।

प्रोफेसर अनंत ने भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और एजेंसियों, भारतीय रिज़र्व बैंक, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग, कई विश्वविद्दालयों के परिषदों और बोर्डों के साथ-साथ अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की विशेषज्ञ समितियों में भी काम किया है।